भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1061
उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

उत्तर प्रदेश में खेल अवसंरचना का विकास

1061. श्री प्रवीण पटेल:
सुश्री इकरा चौधरी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में खेल अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के लिए संस्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं के ब्यौरे सहित परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से खेल अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के जिलों में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाने का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ङ) क्या सरकार का कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, उत्तर प्रदेश राज्य में खेल अवसंरचना के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, यह मंत्रालय खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसे बुनियादी खेल अवसंरचना के निर्माण के साथ-साथ खेल उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। खेलो इंडिया स्कीम

और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित देश भर में जारी की गई धनराशि भी शामिल है, का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमशः https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इन खेल अवसंरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी अनुदान प्राप्तकर्ता की होती है।

(घ) एवं (ङ): जी नहीं, इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****